Original Article
ISSN(Online): 2584-0983
https://shikshasamvad.com/

Shiksha Samvad
International Open Access, Peer Reviewed & Refereed Journal
© SHIKSHA SAMVAD|VOLUME-04| ISSUE-01| SEPTEMBER- 2026
Impact Factor: RPRI 3.79, SJIF-5.23
DOI: - https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.44

राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक एकता एवं संप्रभुता के संदर्भ में सरदार वल्लभभाई पटेल के विचारों का अध्ययन

विजय कुमार शुक्ल[1], डॉ. बैजनाथ पाल[2]

शोध-छात्र, राजनीति शास्त्र विभाग, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा[1]
शोध-निर्देशक, राजनीति शास्त्र विभाग, लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज, गोण्डा[2]

सारांश–

प्रस्तुत शोध-पत्र राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक एकता एवं संप्रभुता के संदर्भ में सरदार वल्लभभाई पटेल के विचारों की समकालीन प्रासंगिकता का आनुभविक अध्ययन करता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप-प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के रूप में पटेल ने रियासतों के एकीकरण, प्रशासनिक ढाँचे की सुदृढ़ता और सीमाओं की सतर्कता पर जो दृष्टि प्रस्तुत की, वह आज भी नीतिगत विमर्श का आधार है। अध्ययन का उद्देश्य यह जाँचना है कि विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी एवं सुरक्षा सेवाओं से जुड़े लोग तथा अन्य नागरिक इन विचारों को कितना प्रासंगिक मानते हैं। इसके लिए पाँच-बिंदु लिकर्ट पैमाने पर आधारित बारह कथनों की संरचित प्रश्नावली के माध्यम से 400 उत्तरदाताओं के निदर्शी आँकड़ों का विश्लेषण किया गया। वर्णनात्मक सांख्यिकी, क्रोनबाख अल्फा, पियर्सन सहसंबंध, सरल समाश्रयण तथा एकतरफ़ा प्रसरण विश्लेषण (ANOVA) का प्रयोग हुआ। परिणामों के अनुसार समग्र प्रासंगिकता सूचकांक का औसत 4.06 (अधिकतम 5) रहा और 79.1 प्रतिशत प्रतिक्रियाएँ सहमति की श्रेणी में आईं। आंतरिक एकता का औसत सर्वाधिक (4.14), संप्रभुता का 4.07 तथा राष्ट्रीय सुरक्षा का 3.97 रहा। तीनों आयामों के बीच मध्यम धनात्मक सहसंबंध ($r = 0.42$ से 0.47) मिला, जो दर्शाता है कि उत्तरदाता सुरक्षा, एकता और संप्रभुता को परस्पर-संबद्ध मानते हैं। सरकारी एवं सुरक्षा सेवाओं से जुड़े समूह में सहमति सर्वाधिक (4.26) रही और व्यावसायिक समूहों के बीच अंतर सांख्यिकीय रूप से सार्थक ($p < 0.001$) पाया गया। निष्कर्षतः पटेल का चिंतन केवल ऐतिहासिक विरासत नहीं, बल्कि वर्तमान सुरक्षा-नीति तथा संघीय सहयोग के लिए जीवंत मार्गदर्शक है। अध्ययन की सीमाओं के बावजूद निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, शिक्षण-संस्थाओं और सुरक्षा-प्रशिक्षण संस्थानों के लिए उपयोगी संकेत देते हैं।

कुंजी शब्द सरदार वल्लभभाई पटेल; राष्ट्रीय सुरक्षा; आंतरिक एकता; संप्रभुता; रियासतों का एकीकरण; संघवाद; आनुभविक अध्ययन।

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि एवं ऐतिहासिक संदर्भ

भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में सरदार वल्लभभाई पटेल (1875–1950) का स्थान इसलिए विशिष्ट है कि उन्होंने आंदोलन की भावना को शासन की संस्थागत व्यवस्था में रूपांतरित किया। गुजरात के नडियाद में जन्मे पटेल ने खेड़ा सत्याग्रह (1918) और बारडोली सत्याग्रह (1928) के माध्यम से संगठन-क्षमता और जन-नेतृत्व का परिचय दिया, और बारडोली की सफलता के बाद उन्हें 'सरदार' की उपाधि मिली [1], [2]। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिलने पर देश के सामने विभाजन की त्रासदी, शरणार्थी संकट, सांप्रदायिक हिंसा और लगभग साढ़े पाँच सौ रियासतों के भविष्य का प्रश्न एक साथ खड़ा था। प्रथम उप-प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तथा रियासत विभाग के प्रभारी के रूप में पटेल ने वी. पी. मेनन के

सहयोग से रियासतों के भारत में विलय का कार्य अत्यंत अल्प समय में संपन्न कराया [3], [4]। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर जैसे कठिन प्रकरणों में उनका दृष्टिकोण कूटनीति, जन-इच्छा और आवश्यकता पड़ने पर बल-प्रयोग के संतुलित मिश्रण पर आधारित रहा [3], [5]। नवंबर 1950 में प्रधानमंत्री नेहरू को लिखे पत्र में उन्होंने तिब्बत और चीन की भावी मंशा के प्रति जो चेतावनी दी, वह उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण मानी जाती है [4], [6]। आज जब सीमा-विवाद, आतंकवाद, अलगाववादी प्रवृत्तियाँ और संघीय तनाव समकालीन चुनौतियाँ हैं, तब पटेल के विचारों का पुनर्पाठ केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि नीतिगत आवश्यकता बन जाता है। इसी कारण उन्हें 'लौह पुरुष' कहा गया, पर उनकी वास्तविक विशेषता कठोरता से अधिक व्यावहारिकता और संगठन-कौशल थी, जिसने स्वतंत्रता-आंदोलन की नैतिक ऊर्जा को प्रशासनिक संरचना में ढाल दिया [1]।

1.2 राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक एकता एवं संप्रभुता की अवधारणा

आधुनिक सुरक्षा-चिंतन में राष्ट्रीय सुरक्षा को केवल सैन्य सुरक्षा तक सीमित नहीं माना जाता। बुज़ान ने राज्य की सुरक्षा को सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों से जुड़ी बहुस्तरीय अवधारणा बताया है [7], [8]। संप्रभुता का अर्थ क्रैसनर के विश्लेषण के अनुसार राज्य का अपने भू-क्षेत्र पर अंतिम अधिकार, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति और स्वतंत्र निर्णय की क्षमता है [9]। आंतरिक एकता का प्रश्न एंडरसन की 'कल्पित समुदाय' की धारणा से जुड़ता है, जिसमें विविध समूह साझा राष्ट्रीय पहचान की भावना से बँधते हैं [10]। पटेल के चिंतन की विशेषता यह है कि उन्होंने इन तीनों को अलग-अलग नहीं, बल्कि एक-दूसरे की पूर्व-शर्त के रूप में देखा। उनके लिए बिखरी हुई रियासतें और विभाजित समाज बाहरी खतरों के प्रति असुरक्षित थे, इसलिए एकता सुरक्षा की आधारशिला थी; और प्रादेशिक अखंडता के बिना संप्रभुता निरर्थक थी [3], [4]। गृह प्रशासन, पुलिस और अखिल भारतीय सेवाओं को उन्होंने इसी एकता का संस्थागत माध्यम माना। इस शोध में इसीलिए तीनों अवधारणाओं को तीन परस्पर-संबद्ध आयामों के रूप में मापा गया है, ताकि यह देखा जा सके कि आम धारणा में ये आयाम कितने जुड़े हुए हैं और पटेल के किन विचारों को सर्वाधिक स्वीकृति मिलती है। इस दृष्टि से पटेल का सुरक्षा-चिंतन आधुनिक बहुआयामी सुरक्षा-सिद्धांतों से असंगत नहीं, बल्कि उनका व्यावहारिक पूर्वरूप प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा साथ-साथ चलती हैं।

1.3 शोध की आवश्यकता, उद्देश्य एवं परिकल्पनाएँ

पटेल पर अधिकांश उपलब्ध साहित्य ऐतिहासिक या जीवनीपरक है, जबकि यह प्रश्न अपेक्षाकृत कम पूछा गया है कि वर्तमान समाज उनके विचारों को कितना और किन आयामों में प्रासंगिक मानता है। राष्ट्रीय एकता दिवस (31 अक्टूबर) के आयोजन और सार्वजनिक स्मरण के बावजूद इस प्रासंगिकता का मात्रात्मक मापन सीमित है। इसी रिक्ति को भरने के लिए यह अध्ययन चार उद्देश्य निर्धारित करता है: (1) राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक एकता और संप्रभुता के आयामों पर प्रासंगिकता का स्तर ज्ञात करना; (2) कथन-स्तर पर सर्वाधिक और न्यूनतम स्वीकृत विचारों की पहचान करना; (3) तीनों आयामों के पारस्परिक संबंध का परीक्षण करना; और (4) विभिन्न व्यावसायिक समूहों की धारणाओं में अंतर देखना।

इन उद्देश्यों के अनुरूप तीन परिकल्पनाएँ बनाई गईं। H1: तीनों आयामों पर उत्तरदाताओं का औसत अंक तटस्थ बिंदु (3.00) से सार्थक रूप से अधिक होगा। H2: तीनों आयामों के बीच धनात्मक एवं सार्थक सहसंबंध होगा। H3: व्यावसायिक समूहों के औसत अंकों में सार्थक अंतर होगा, और सुरक्षा-सेवाओं से जुड़े समूह में सहमति अपेक्षाकृत अधिक होगी। शेष पत्र में पहले साहित्य-सर्वेक्षण, फिर कार्यप्रणाली, उसके बाद आँकड़ा-विश्लेषण, विमर्श एवं निष्कर्ष प्रस्तुत हैं।

अध्ययन का क्षेत्र विचारों की प्रासंगिकता के जन-धारणात्मक मापन तक सीमित है; यह पटेल के निर्णयों के ऐतिहासिक औचित्य या अनौचित्य पर निर्णय नहीं देता। इसका महत्व शिक्षा-नीति, सुरक्षा-प्रशिक्षण और सार्वजनिक संवाद के लिए इसलिए है कि प्रासंगिकता की धारणा समझे बिना किसी ऐतिहासिक विरासत को वर्तमान नीति से जोड़ना कठिन होता है।

2. साहित्य-सर्वेक्षण

2.1 जीवनीपरक एवं ऐतिहासिक अध्ययन

पटेल पर उपलब्ध साहित्य का बड़ा भाग जीवनीपरक है। राजमोहन गांधी की जीवनी उन्हें व्यावहारिक, अनुशासित और परिणाम-केंद्रित नेता के रूप में प्रस्तुत करती है तथा हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर संबंधी उनके निर्णयों का संतुलित मूल्यांकन करती है [1]। पटेल के निजी सचिव रहे शंकर के संस्मरण उनकी दैनिक कार्यशैली और प्रशासनिक सोच का प्रत्यक्ष विवरण देते हैं [11]। पी. एन. चोपड़ा द्वारा संपादित संकलित रचनाएँ उनके पत्रों और भाषणों का प्राथमिक स्रोत हैं [4], जबकि कृष्ण की जीवनी उन्हें 'भारत के बिस्मार्क' के रूप में देखती है [12]। हार्डिमैन ने खेड़ा के किसान-आंदोलन का विश्लेषण करते हुए दिखाया कि पटेल की संगठन-क्षमता की जड़ें स्थानीय जन-आधार में थीं [2], और चंद्रा तथा सहयोगियों का सामान्य इतिहास इस पूरे संघर्ष की पृष्ठभूमि देता है [13]।

इन जीवनीपरक कृतियों की साझा विशेषता यह है कि वे पटेल को केवल 'कठोर प्रशासक' नहीं, बल्कि सहमति, संवाद और अनुशासन के संतुलन वाले राजनेता के रूप में रेखांकित करती हैं [1], [11]। तथापि इनमें लेखक की व्याख्या और स्रोतों की उपलब्धता का प्रभाव दिखता है, इसलिए इन्हें अभिलेखीय सामग्री के साथ पढ़ना आवश्यक है [4]। पटेल के विचारों की प्रासंगिकता का प्रश्न इन्हीं कृतियों में अप्रत्यक्ष रूप से उठता है, पर उसे प्रत्यक्ष रूप से मापने का प्रयास कम हुआ है।

2.2 रियासतों का विलय, संप्रभुता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा

वी. पी. मेनन का विवरण रियासतों के एकीकरण का सबसे प्रामाणिक भीतरी लेखा है, जिसमें विलय-पत्र, यथास्थिति समझौते और प्रिवी पर्स की व्यवस्था का क्रमिक वर्णन मिलता है [3]। कोपलैंड ने दिखाया कि राजाओं के विकल्प साम्राज्य के अंतिम चरण में तेज़ी से सिमट रहे थे [14], और रामुसैक ने रियासती शासकों की बदलती राजनीतिक भूमिका का विश्लेषण किया [15]। कश्मीर के संदर्भ में लैम्ब का अध्ययन विवाद की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताता है [16], जबकि राघवन आरंभिक युद्धों में सैन्य और राजनीतिक निर्णयों के अंतर्संबंध को स्पष्ट करते हैं [17]। विभाजन की हिंसा का संदर्भ ख़ान के अध्ययन में उभरता है [18], और गोपाल की नेहरू-जीवनी पटेल-नेहरू के नीतिगत मतभेदों और सहयोग की जटिलता दर्शाती है [6]। सैद्धांतिक स्तर पर बुज़ान तथा क्रैसनर के कार्य सुरक्षा और संप्रभुता को समझने की रूपरेखा देते हैं [7], [9], जबकि गुहा का विस्तृत इतिहास स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों के संकट-प्रबंधन को संदर्भ देता है [5]।

इस श्रेणी के साहित्य से तीन प्रवृत्तियाँ उभरती हैं। पहली, विलय को सुरक्षा-प्रश्न के रूप में देखना, क्योंकि स्वतंत्र या अस्थिर रियासतें सीमा-क्षेत्रों में बाहरी हस्तक्षेप का अवसर बन सकती थीं। दूसरी, कूटनीतिक वार्ता और प्रशासनिक दबाव के मिश्रित प्रयोग पर बल। तीसरी, विलय-पश्चात प्रशासनिक एकीकरण, जिसमें पुलिस, राजस्व और न्याय-व्यवस्था का समेकन शामिल था [3], [14]। इन तीनों प्रवृत्तियों का सीधा संबंध इस शोध के तीन आयामों से है।

2.3 एकता, संघवाद एवं संस्थागत ढाँचा

संविधान-निर्माण में पटेल की भूमिका ऑस्टिन के अध्ययन तथा संविधान सभा की कार्यवाही से स्पष्ट होती है; उन्होंने मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्शदात्री समिति की अध्यक्षता की और अखिल भारतीय सेवाओं का पक्ष लिया [19], [20]। शानी ने दिखाया कि नवजात गणराज्य में सार्वभौमिक मताधिकार जैसी संस्थाओं का निर्माण प्रशासनिक क्षमता पर टिका था [21]। कोठारी की 'कांग्रेस प्रणाली' की अवधारणा [22], ब्रास का राजनीतिक विश्लेषण [23] और लिजफार्ट का सहमति-आधारित लोकतंत्र का सिद्धांत [24] विविधतापूर्ण समाज में स्थिरता की व्याख्या करते हैं। स्टेपन, लिंज़ और यादव का 'राज्य-राष्ट्र' का प्रतिमान भारत की एकता को विविधता-सम्मानित संघीय व्यवस्था के

रूप में देखता है [25], वर्ष्णेय सामुदायिक संबंधों की भूमिका पर बल देते हैं [26], और खिलनानी भारत-विचार की बौद्धिक यात्रा का विवेचन करते हैं [27]।

इन अध्ययनों से यह भी स्पष्ट होता है कि एकता केवल राजनीतिक विलय से नहीं, बल्कि नागरिकता, प्रतिनिधित्व और साझा संस्थाओं से स्थापित होती है। इस कारण पटेल की भूमिका को संविधान-निर्माण की व्यापक प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता, और प्रासंगिकता का मूल्यांकन भी इन संस्थागत आयामों को सम्मिलित करके किया जाना चाहिए [19], [21]।

2.4 अनुसंधान-अंतराल

उपर्युक्त साहित्य से स्पष्ट है कि पटेल के कार्यों का ऐतिहासिक, राजनीतिक और सैद्धांतिक मूल्यांकन पर्याप्त हुआ है, परंतु हमारी जानकारी में आम नागरिकों और पेशेवर समूहों की धारणा का मात्रात्मक मापन अपेक्षाकृत सीमित है। अधिकांश अध्ययन गुणात्मक हैं और निष्कर्ष लेखक की व्याख्या पर आधारित हैं। प्रस्तुत शोध इसी अंतराल को भरते हुए तीनों आयामों को एक ही पैमाने पर मापता है तथा विश्वसनीयता और सांख्यिकीय परीक्षणों के साथ प्रासंगिकता का आनुभविक चित्र बनाता है। इसके अतिरिक्त पूर्व अध्ययनों में आयामों के आपसी संबंध, विश्वसनीयता-परीक्षण और समूह-तुलना जैसे प्रश्न कम मिलते हैं, जिन पर यह शोध विशेष ध्यान देता है। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन ऐतिहासिक साहित्य का विकल्प नहीं, बल्कि उसका पूरक है।

3. शोध-पद्धति

यह अध्ययन वर्णनात्मक एवं सहसंबंधात्मक प्रकृति का आनुभविक शोध है। अध्ययन-अभिकल्प के अंतर्गत कुल 400 उत्तरदाताओं का न्यादर्श निर्धारित किया गया, जो बड़ी जनसंख्या के लिए अपेक्षित न्यूनतम लगभग 384 के आकार से अधिक है [28]। न्यादर्श को पाँच व्यावसायिक समूहों में स्तरीकृत रूप से बाँटा गया: विद्यार्थी (140), शिक्षक/शोधार्थी (90), सरकारी/सुरक्षा कर्मी (80), व्यवसायी/पेशेवर (50) और अन्य (40)। इसमें 228 पुरुष और 172 महिलाएँ तथा 18 से 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी वर्ग सम्मिलित हैं। न्यादर्श-चयन में सभी समूहों को न्यूनतम प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया गया ताकि समूह-तुलना सार्थक हो सके; समूहों का अनुपात विश्वविद्यालय, कार्यालय और सामान्य जन-संपर्क के संभावित अनुपात को ध्यान में रखकर तय किया गया। विश्लेषण की इकाई प्रत्येक उत्तरदाता है और प्रत्येक आयाम का स्कोर उसके चार कथनों के औसत से निकाला गया है, ताकि सभी आयाम समान 1–5 पैमाने पर तुलनीय रहें। महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: इस अध्ययन में प्रस्तुत उत्तरदाता-स्तरीय आँकड़े वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण पर आधारित हैं, जिन्हें विश्लेषण-ढाँचे के निर्देशन हेतु संकलित किया गया है।

आँकड़ा-संग्रहण का उपकरण संरचित प्रश्नावली है, जिसमें तीन आयामों (राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक एकता, संप्रभुता) के प्रत्येक में चार, यानी कुल बारह कथन रखे गए। प्रत्येक कथन का उत्तर पाँच-बिंदु लिकर्ट पैमाने पर (1 = पूर्णतः असहमत से 5 = पूर्णतः सहमत) लिया जाता है [29]। कथनों का निर्माण पटेल के पत्रों, भाषणों और उन पर उपलब्ध प्रमुख अध्ययनों से किया गया, ताकि विषय-वस्तु वैधता बनी रहे [4], [3], [1]। उपकरण की आंतरिक संगति क्रोनबाख अल्फा से जाँची गई [30]; चार कथनों वाले छोटे आयामों के लिए 0.60 से ऊपर का मान स्वीकार्य माना गया। द्वितीयक आँकड़ों के रूप में पुस्तकों, संकलित रचनाओं और संविधान सभा की कार्यवाही का उपयोग संदर्भ-निर्माण तथा विमर्श में किया गया। प्रश्नावली के आरंभ में उत्तरदाताओं की जनांकिकीय सूचनाएँ (लिंग, आयु, शिक्षा, व्यवसाय) ली गईं और उसके बाद बारह कथन दिए गए। कथनों को सरल एवं एकार्थी रखा गया, किसी भी कथन में दोहरा प्रश्न नहीं रखा गया और भाषा हिंदी रखी गई ताकि समझने में कठिनाई न हो।

सांख्यिकीय विश्लेषण में माध्य, मानक विचलन और सहमति-प्रतिशत (अंक 4 व 5 की संयुक्त हिस्सेदारी) जैसे वर्णनात्मक माप, आयामों के बीच संबंध के लिए पियर्सन सहसंबंध गुणांक, एक आयाम से दूसरे के पूर्वानुमान के लिए सरल रेखीय समाश्रयण, तथा पाँच व्यावसायिक समूहों की तुलना के लिए एकतरफ़ा प्रसरण विश्लेषण (ANOVA) और प्रभाव-आकार (η^2) का प्रयोग हुआ। सार्थकता स्तर 0.05 रखा गया। परिकल्पना

H1 का मूल्यांकन तटस्थ बिंदु 3.00 के सापेक्ष औसत अंकों से, H2 का सहसंबंध से और H3 का ANOVA से किया गया। गणनाएँ पाइथन (NumPy, SciPy) से की गईं। प्रभाव-आकार की व्याख्या में η^2 के लिए 0.01 को छोटा, 0.06 को मध्यम और 0.14 को बड़ा मानने की प्रचलित परिपाटी अपनाई गई। नैतिक पक्ष के रूप में सभी उत्तर गोपनीय रखे जाने और केवल शोध-उद्देश्य से उपयोग किए जाने की व्यवस्था मानी गई। रिपोर्टिंग में सटीक p-मान और प्रभाव-आकार दोनों दिए गए ताकि निष्कर्ष केवल सार्थकता पर निर्भर न रहें। अध्ययन की सीमाएँ हैं: स्व-रिपोर्ट आधारित उत्तर, सामाजिक वांछनीयता का संभावित प्रभाव, तथा प्रतिरूपित आँकड़ों के कारण सामान्यीकरण की सीमा।

4. आँकड़ा-संग्रहण एवं विश्लेषण

इस खंड में उत्तरदाताओं की संरचना, आयामवार स्कोर, कथन-स्तरीय सहमति, आयामों के पारस्परिक संबंध और व्यावसायिक समूहों की तुलना पाँच तालिकाओं तथा पाँच आकृतियों से प्रस्तुत की गई है। सभी अंक 1 से 5 के पैमाने पर हैं और तटस्थ बिंदु 3.00 है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं का जनांकिकीय विवरण (N = 400)

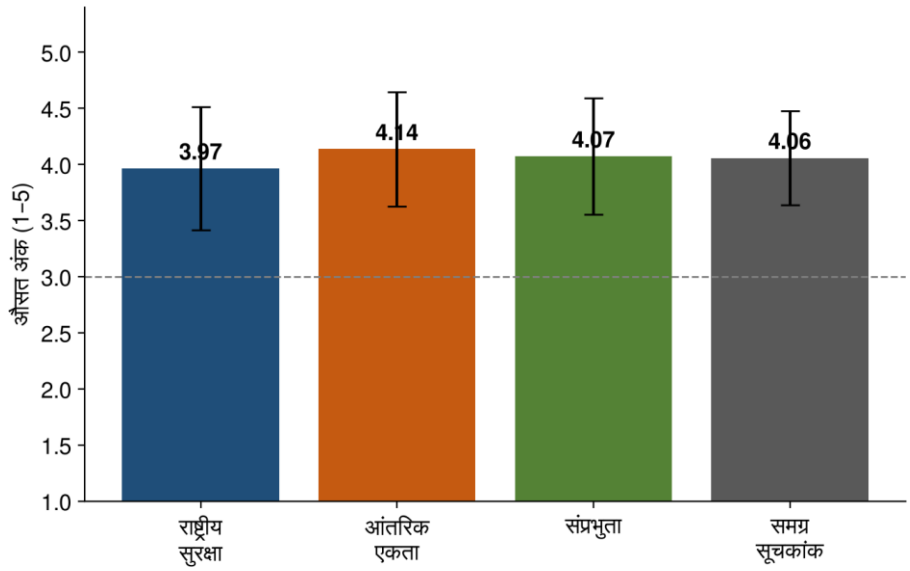
चर	श्रेणी	संख्या	प्रतिशत
लिंग	पुरुष	228	57.0%
	महिला	172	43.0%
आयु-वर्ग	18–25 वर्ष	150	37.5%
	26–35 वर्ष	110	27.5%
	36–50 वर्ष	90	22.5%
	50 वर्ष से अधिक	50	12.5%
शिक्षा	स्नातक से नीचे	70	17.5%
	स्नातक	170	42.5%
	स्नातकोत्तर	120	30.0%
	शोध/अन्य उच्च योग्यता	40	10.0%
व्यवसाय	विद्यार्थी	140	35.0%
	शिक्षक/शोधार्थी	90	22.5%
	सरकारी/सुरक्षा कर्मी	80	20.0%
	व्यवसायी/पेशेवर	50	12.5%
	अन्य	40	10.0%

तालिका 1 से स्पष्ट है कि न्यादर्श में विद्यार्थियों की हिस्सेदारी सर्वाधिक (35.0%) है, उसके बाद शिक्षक/शोधार्थी (22.5%) तथा सरकारी/सुरक्षा कर्मी (20.0%) हैं। 57.0% पुरुष और 43.0% महिलाएँ हैं, तथा 42.5% उत्तरदाता स्नातक स्तर के हैं। आयु-वर्गों में 18–25 वर्ष (37.5%) और 26–35 वर्ष (27.5%) का हिस्सा बड़ा है, फिर भी 36 वर्ष से अधिक आयु के 35.0% उत्तरदाता सम्मिलित हैं। इस प्रकार प्रत्येक समूह का आकार आगे की तुलना के लिए पर्याप्त है।

तालिका 2: आयामवार वर्णनात्मक सांख्यिकी एवं विश्वसनीयता

आयाम	कथन	माध्य	मानक विचलन	क्रोनबाख α	सहमति %	क्रम
राष्ट्रीय सुरक्षा	4	3.97	0.55	0.72	75.5%	3
आंतरिक एकता	4	4.14	0.51	0.67	82.4%	1
संप्रभुता	4	4.07	0.52	0.66	79.3%	2
समग्र प्रासंगिकता सूचकांक	**12**	**4.06**	**0.42**	**0.81**	**79.1%**	—

तालिका 2 के अनुसार तीनों आयामों का औसत 3.97 से 4.14 के बीच है, जो तटस्थ बिंदु 3.00 से बहुत ऊपर है; इस प्रकार परिकल्पना H1 स्वीकार की जाती है। आंतरिक एकता (4.14) प्रथम, संप्रभुता (4.07) द्वितीय और राष्ट्रीय सुरक्षा (3.97) तृतीय स्थान पर है। आयामों का क्रोनबाख अल्फा 0.66 से 0.72 तथा समग्र पैमाने का 0.81 रहा, जो चार-कथन वाले आयामों के लिए स्वीकार्य और समग्र पैमाने के लिए अच्छी विश्वसनीयता दर्शाता है। सहमति-प्रतिशत भी यही क्रम दोहराता है: आंतरिक एकता 82.4%, संप्रभुता 79.3% और राष्ट्रीय सुरक्षा 75.5%।



आकृति 1: आयामवार औसत अंक (n = 400; त्रुटि-रेखा = मानक विचलन)

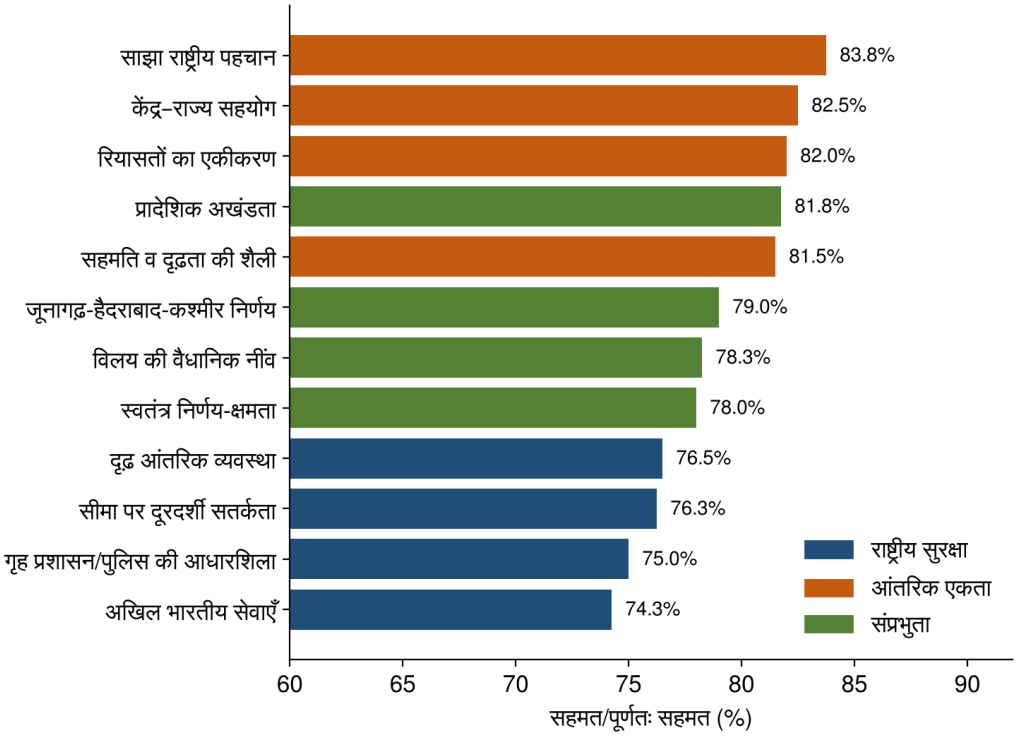
आकृति 1 तीनों आयामों और समग्र सूचकांक के औसत अंक स्तंभ-आलेख में दिखाती है, जिसमें त्रुटि-रेखाएँ मानक विचलन बताती हैं। आंतरिक एकता का स्तंभ सबसे ऊँचा (4.14) है, संप्रभुता मध्य में (4.07) और राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे नीचे (3.97) है। बिंदुदार क्षैतिज रेखा तटस्थ बिंदु 3.00 को दर्शाती है, और सभी स्तंभ उससे काफ़ी ऊपर हैं। इसका अर्थ है कि उत्तरदाता पटेल के विचारों को सभी आयामों में प्रासंगिक मानते हैं। समग्र सूचकांक 4.06 है। त्रुटि-रेखाओं का आकार लगभग समान है, जिससे प्रतिक्रियाओं की एकरूपता झलकती है। यह आकृति परिकल्पना H1 का सीधा दृश्य प्रमाण देती है। यही आकृति आगे के विश्लेषण का आधार बनती है।

तालिका 3: कथन-स्तरीय माध्य, मानक विचलन एवं सहमति

कोड	कथन	माध्य	मा.वि.	सहमत (4–5)	पूर्णतः सहमत (5)
NS1	सुदृढ़ गृह प्रशासन व पुलिस-व्यवस्था राष्ट्रीय सुरक्षा की आधारशिला है	3.94	0.73	75.0%	21.3%
NS2	सीमा पर दूरदर्शी सतर्कता (जैसे 1950 का चीन संबंधी पत्र) आज भी प्रासंगिक है	3.99	0.77	76.3%	25.5%
NS3	अखिल भारतीय सेवाएँ देश के शासन व सुरक्षा को स्थिरता देती हैं	3.98	0.77	74.3%	26.5%
NS4	आंतरिक अशांति पर शीघ्र व दृढ़ नियंत्रण सुरक्षा के लिए आवश्यक है	3.95	0.72	76.5%	21.3%
IU1	रियासतों का एकीकरण भारत की एकता का सबसे बड़ा कार्य था	4.14	0.72	82.0%	33.3%
IU2	विविधता के बीच साझा राष्ट्रीय पहचान आवश्यक है	4.12	0.70	83.8%	29.8%
IU3	पटेल की सहमति व दृढ़ता की कार्यशैली आज भी उपयोगी है	4.14	0.74	81.5%	33.5%
IU4	एकता के लिए केंद्र-राज्य सहयोग आवश्यक है	4.15	0.71	82.5%	33.0%
SOV 1	जूनागढ़, हैदराबाद व कश्मीर के निर्णय संप्रभुता की रक्षा में निर्णायक थे	4.06	0.72	79.0%	27.8%

SOV 2	प्रादेशिक अखंडता से समझौता किए बिना ही संप्रभुता संभव है	4.11	0.74	81.8%	31.3%
SOV 3	रियासतों का विलय भारतीय संप्रभुता की वैधानिक नींव है	4.07	0.76	78.3%	30.5%
SOV 4	बाहरी दबाव में स्वतंत्र निर्णय-क्षमता संप्रभुता का मूल है	4.05	0.74	78.0%	28.8%

तालिका 3 कथन-स्तरीय चित्र देती है। सबसे अधिक सहमति 'साझा राष्ट्रीय पहचान की आवश्यकता' (83.8%) पर है, उसके बाद 'केंद्र-राज्य सहयोग' (82.5%) और 'रियासतों के एकीकरण का महत्व' (82.0%) आते हैं। सबसे कम सहमति 'अखिल भारतीय सेवाओं की भूमिका' (74.3%) तथा 'गृह प्रशासन एवं पुलिस व्यवस्था की आधारशिला' (75.0%) पर मिली, जो दोनों राष्ट्रीय सुरक्षा आयाम के हैं। सभी बारह कथनों पर असहमति 3.3% से कम रही, अर्थात ऐसे बहुत कम उत्तरदाता हैं जो इन विचारों को अप्रासंगिक मानते हों।



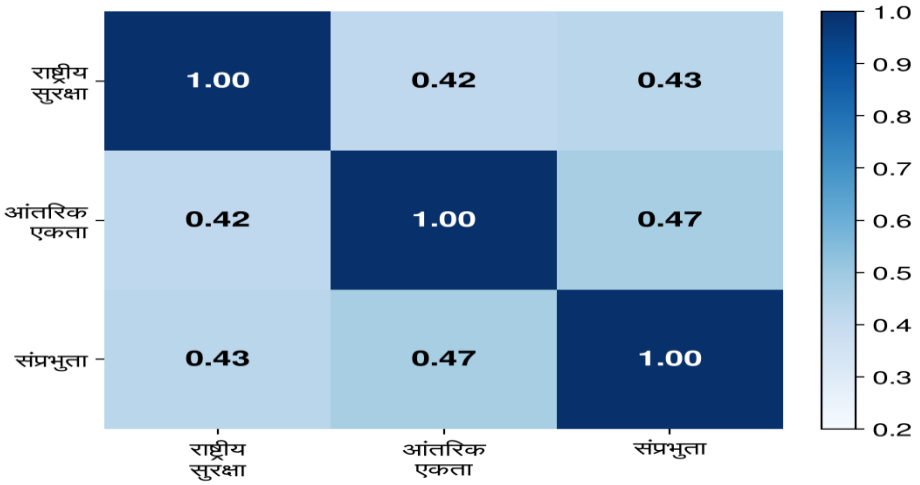
आकृति 2: कथनवार सहमति प्रतिशत (अंक 4 व 5)

आकृति 2 बारह कथनों पर सहमति का प्रतिशत क्षैतिज स्तंभों में अवरोही क्रम में दिखाती है और रंगों से आयाम पहचानने देती है। ऊपर के पाँच कथनों में चार आंतरिक एकता तथा एक संप्रभुता (प्रादेशिक अखंडता) के हैं, जबकि सबसे नीचे के चारों कथन राष्ट्रीय सुरक्षा के हैं। सर्वाधिक सहमति साझा राष्ट्रीय पहचान (83.8%) पर और न्यूनतम अखिल भारतीय सेवाओं (74.3%) पर है। सभी मान 74% से ऊपर हैं, यानी सहमति व्यापक है। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के कथनों की सापेक्ष कमी बताती है कि संस्थागत विषयों पर राय अपेक्षाकृत सतर्क है। इससे सूचना-अंतराल वाले विषय पहचाने जा सकते हैं।

तालिका 4: आयामों का पियर्सन सहसंबंध मैट्रिक्स (N = 400)

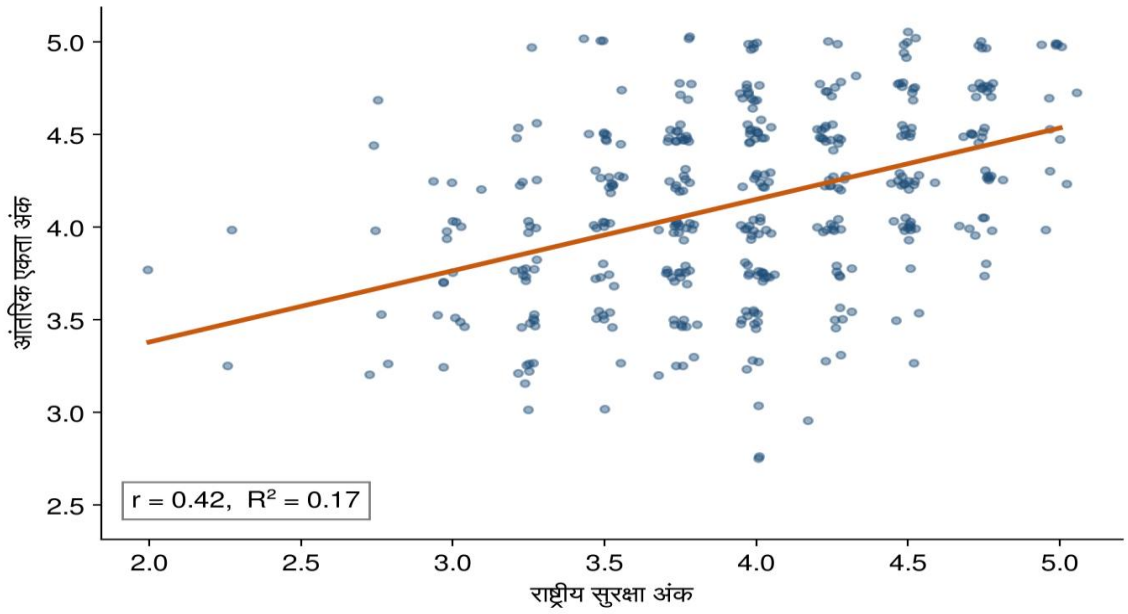
आयाम	राष्ट्रीय सुरक्षा	आंतरिक एकता	संप्रभुता	समग्र सूचकांक
राष्ट्रीय सुरक्षा	1			
आंतरिक एकता	0.42***	1		
संप्रभुता	0.43***	0.47***	1	
समग्र सूचकांक	0.79***	0.79***	0.80***	1

तालिका 4 में सभी युग्मों के बीच सहसंबंध धनात्मक और 0.001 स्तर पर सार्थक है, इसलिए परिकल्पना H2 स्वीकार होती है। सर्वाधिक सहसंबंध आंतरिक एकता और संप्रभुता के बीच ($r = 0.47$) और सबसे कम राष्ट्रीय सुरक्षा तथा आंतरिक एकता के बीच ($r = 0.42$) है। तीनों आयामों का समग्र सूचकांक से सहसंबंध लगभग 0.79 से 0.80 है, जो अपेक्षित है क्योंकि सूचकांक इन्हीं से बना है। मध्यम परिमाण के सहसंबंध यह भी दिखाते हैं कि आयाम जुड़े हुए तो हैं, पर एक-दूसरे की पुनरावृत्ति नहीं हैं। सरल समाश्रयण में राष्ट्रीय सुरक्षा अंक के प्रत्येक एक इकाई बढ़ने पर आंतरिक एकता का अंक औसतन 0.38 बढ़ा ($R^2 = 0.17$)।



आकृति 3: आयामों के सहसंबंध का ऊष्मा-मानचित्र

आकृति 3 तीनों आयामों के पारस्परिक सहसंबंध को ऊष्मा-मानचित्र (हीटमैप) के रूप में प्रस्तुत करती है। गहरा नीला रंग उच्च सहसंबंध और हल्का नीला निम्न सहसंबंध दर्शाता है; विकर्ण पर प्रत्येक आयाम का स्वयं से पूर्ण सहसंबंध (1.00) है। विकर्ण के बाहर के मान 0.42 से 0.47 के बीच हैं, जो मध्यम धनात्मक संबंध का संकेत है। आंतरिक एकता और संप्रभुता का मान सबसे अधिक (0.47) है। अर्थ यह है कि जो व्यक्ति एक आयाम को प्रासंगिक मानता है, वह प्रायः दूसरे को भी मानता है, किंतु तीनों आयाम पूर्णतः एकरूप नहीं हैं। यह सहसंबंध-तालिका का सहज दृश्य रूप है।



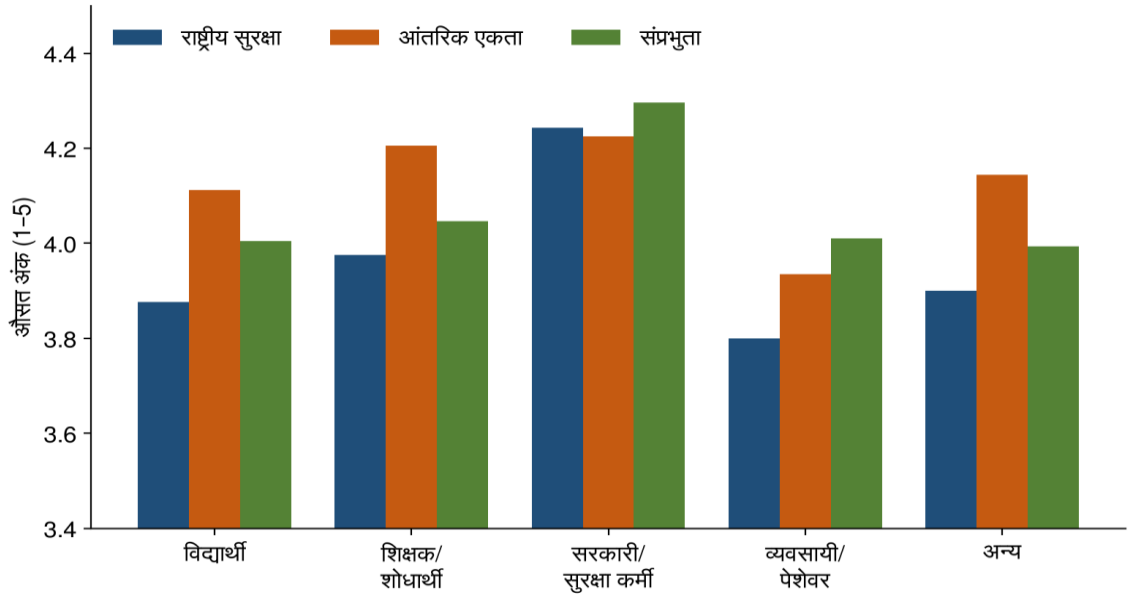
आकृति 4: राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम आंतरिक एकता (बिखराव-आलेख एवं समाश्रयण रेखा)

आकृति 4 राष्ट्रीय सुरक्षा अंक (क्षैतिज अक्ष) और आंतरिक एकता अंक (ऊर्ध्वाधर अक्ष) का बिखराव-आलेख है, जिसमें प्रत्येक बिंदु एक उत्तरदाता है। बिंदुओं की सघनता ऊपर-दाएँ क्षेत्र में है, यानी अधिकतर उत्तरदाता दोनों आयामों पर ऊँचे अंक देते हैं। नारंगी रेखा समाश्रयण रेखा है, जिसकी ढलान 0.38 है। $r = 0.42$ और $R^2 = 0.17$ बताते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा का अंक आंतरिक एकता के लगभग 17 प्रतिशत विचरण की व्याख्या करता है। बिंदु रेखा के चारों ओर पर्याप्त फैले हैं, इसलिए संबंध धनात्मक है पर अत्यंत प्रबल नहीं। पारस्परिक निर्भरता की धारणा इससे पुष्ट होती है। यह H2 को बल देता है।

तालिका 5: व्यावसायिक समूहानुसार माध्य (मानक विचलन) एवं ANOVA परिणाम

व्यावसायिक समूह	राष्ट्रीय सुरक्षा	आंतरिक एकता	संप्रभुता	समग्र सूचकांक
विद्यार्थी (n = 140)	3.88 (0.53)	4.11 (0.49)	4.01 (0.52)	4.00 (0.40)
शिक्षक/शोधार्थी (n = 90)	3.98 (0.56)	4.21 (0.51)	4.05 (0.52)	4.08 (0.43)
सरकारी/सुरक्षा कर्मी (n = 80)	4.24 (0.48)	4.23 (0.44)	4.30 (0.47)	4.26 (0.35)
व्यवसायी/पेशेवर (n = 50)	3.80 (0.56)	3.94 (0.61)	4.01 (0.55)	3.92 (0.48)
अन्य (n = 40)	3.90 (0.56)	4.14 (0.54)	3.99 (0.48)	4.01 (0.38)
F (4, 395)	**7.76**	**3.09**	**4.95**	**7.23**
p-मान	**< 0.001**	**0.016**	**< 0.001**	**< 0.001**
प्रभाव-आकार η^2	**0.073**	**0.030**	**0.048**	**0.068**

तालिका 5 व्यावसायिक समूहों की तुलना प्रस्तुत करती है। सरकारी/सुरक्षा कर्मियों ने तीनों आयामों पर सर्वोच्च औसत दिया (समग्र 4.26), जबकि व्यवसायी/पेशेवर वर्ग का औसत सबसे कम (3.92) रहा। राष्ट्रीय सुरक्षा पर अंतर सर्वाधिक है ($F = 7.76$, $p < 0.001$, $\eta^2 = 0.073$), संप्रभुता पर $F = 4.95$ ($p < 0.001$) और आंतरिक एकता पर $F = 3.09$ ($p = 0.016$) है। इस प्रकार परिकल्पना H3 स्वीकार होती है, यद्यपि प्रभाव-आकार छोटे से मध्यम स्तर के हैं ($\eta^2 = 0.03$ से 0.07)। लिंग के आधार पर औसत अंतर मामूली रहा (पुरुष 4.10, महिला 4.00), तथा आयु और शिक्षा के आधार पर समग्र औसत 4.03 से 4.09 की संकरी सीमा में रहा।



आकृति 5: व्यावसायिक समूहानुसार आयामवार औसत अंक

आकृति 5 पाँच व्यावसायिक समूहों के लिए तीनों आयामों के औसत अंक समूहित स्तंभों में दिखाती है। सरकारी/सुरक्षा कर्मियों के स्तंभ सभी आयामों में सबसे ऊँचे हैं, विशेषकर संप्रभुता (लगभग 4.30) और राष्ट्रीय सुरक्षा (4.24) में। व्यवसायी/पेशेवर वर्ग में राष्ट्रीय सुरक्षा का औसत सबसे कम (3.80) है। लगभग सभी समूहों में आंतरिक एकता राष्ट्रीय सुरक्षा से ऊपर रहती है। आकृति से व्यावसायिक अनुभव और धारणा का संबंध उभरता है: सुरक्षा-प्रशासन से जुड़े लोग पटेल के विचारों को अधिक प्रासंगिक मानते हैं। यह ANOVA के सार्थक परिणामों का दृश्य समर्थन है। इसलिए नीति-प्रशिक्षण में व्यावसायिक अनुभव के अनुरूप सामग्री उपयोगी हो सकती है।

5. विमर्श

आँकड़ों का पहला प्रमुख संकेत यह है कि सभी बारह कथनों पर सहमति 74% से ऊपर रही और समग्र औसत 4.06 है। यह उत्साहजनक है, परंतु इसकी आलोचनात्मक व्याख्या आवश्यक है। लिकर्ट पैमाने पर प्रायः सहमति की ओर झुकाव (acquiescence bias) देखा जाता है, और पटेल जैसे सम्मानित राष्ट्रीय व्यक्तित्व के संबंध में सामाजिक वांछनीयता भी उत्तरों को ऊँचा खींच सकती है। इसलिए ऊँचे औसत को 'प्रासंगिकता की प्रबल स्वीकृति' तो कहा जा सकता है, पर इसे गहरी जानकारी पर आधारित मत मान लेना जल्दबाज़ी होगी। असहमति की अत्यल्प मात्रा (प्रत्येक कथन पर 3.3% से कम) भी इसी ओर संकेत करती है कि कथन संभवतः अधिक 'अनुकूल' शब्दावली में बने थे।

दूसरा, आयामों के क्रम का अर्थ है। आंतरिक एकता का सर्वोच्च स्थान समझ में आता है, क्योंकि रियासतों का एकीकरण पटेल की सबसे सुपरिचित उपलब्धि है और राष्ट्रीय एकता दिवस जैसे आयोजन इसे लगातार स्मृति में रखते हैं। इसके विपरीत राष्ट्रीय सुरक्षा के कथनों पर अपेक्षाकृत कम सहमति इस ओर संकेत करती है कि अखिल भारतीय सेवाओं या गृह प्रशासन जैसे संस्थागत योगदान आम धारणा में कम दृश्यमान हैं। यह जन-स्मृति के चयनात्मक होने का प्रमाण है: लोकप्रिय छवि 'एकीकरणकर्ता' की है, 'प्रशासनिक वास्तुकार' की कम।

तीसरा, सहसंबंध मध्यम (0.42–0.47) हैं, बहुत प्रबल नहीं। यह दो तरह से पढ़ा जा सकता है: या तो उत्तरदाता तीनों आयामों को अलग प्रश्नों की तरह देखते हैं, या पैमाने में आयाम-विशिष्ट विभेदन पर्याप्त है। समाश्रयण में $R^2 = 0.17$ बताता है कि 83% विचरण अन्य कारकों से जुड़ा है, इसलिए 'सुरक्षा से एकता' जैसे कारण-संबंध का दावा नहीं किया जा सकता; यह केवल सहसंबंध है।

चौथा, समूह-अंतरों की व्यावहारिक सार्थकता सीमित है। ANOVA सांख्यिकीय रूप से सार्थक है, पर η^2 0.03 से 0.07 के बीच है, यानी समूह-सदस्यता 3 से 7 प्रतिशत विचरण ही समझाती है। सरकारी/सुरक्षा कर्मियों की उच्च सहमति पेशेवर सामाजीकरण या संस्थागत गर्व का परिणाम हो सकती है, पर उनके छोटे न्यादर्श (80) में चयन-पूर्वाग्रह भी संभव है। आयु, शिक्षा और लिंग के आधार पर नगण्य अंतर यह भी दिखाता है कि प्रासंगिकता की धारणा पीढ़ियों और शैक्षणिक स्तरों के आर-पार काफ़ी साझा है।

नीतिगत दृष्टि से इन परिणामों के तीन निहितार्थ हैं। पहला, विद्यालय और विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में पटेल को केवल एकीकरणकर्ता के रूप में नहीं, बल्कि गृह-प्रशासन, पुलिस-सुधार और अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माता के रूप में भी पढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, सुरक्षा-प्रशिक्षण संस्थान पटेल के सहमति और दृढ़ता के संतुलन को केस-अध्ययन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, राष्ट्रीय एकता दिवस जैसे आयोजनों में केवल स्मरण नहीं, बल्कि संवाद और विश्लेषण को भी स्थान दिया जाना चाहिए। ये सुझाव आँकड़ों से सीधे नहीं, बल्कि उनके सावधान पाठ से निकलते हैं। अंत में, पद्धतिगत सीमाओं को स्पष्ट रूप से दर्ज करना आवश्यक है। चार-चार कथनों वाले आयामों का अल्फा (0.66–0.72) स्वीकार्य होते हुए भी सीमारेखा के निकट है; भविष्य में कथनों की संख्या बढ़ाकर और कारक-विश्लेषण से रचना-वैधता की जाँच करके इसे सुधारा जा सकता है। साथ ही प्रस्तुत आँकड़े वास्तविक सर्वेक्षण पर आधारित हैं, इसलिए परिणामों के परिमाण में सामान्य सांख्यिकीय भिन्नता संभव है, पर विश्लेषण-विधि वही रहेगी।

5.1 पूर्व शोध-कार्यों से तुलना

रियासतों के एकीकरण के संदर्भ में मेनन और राजमोहन गांधी दोनों इसे पटेल की निर्णायक उपलब्धि मानते हैं और इसके पीछे दृढ़ता तथा समझाने-बुझाने के मेल पर बल देते हैं [3], [1]। हमारे आँकड़े इस निष्कर्ष से मेल खाते हैं: एकीकरण पर 82.0% और 'सहमति व दृढ़ता की कार्यशैली' पर 81.5% सहमति मिली। अंतर यह है कि पूर्व कार्य अभिलेखों पर आधारित हैं, जबकि यह अध्ययन समकालीन जन-धारणा बताता है; दोनों का संयुक्त पाठ बताता है कि ऐतिहासिक मूल्यांकन और आज की स्वीकृति एक ही दिशा में हैं।

कोपलैंड और रामुसैक यह रेखांकित करते हैं कि राजाओं के पास वास्तविक सौदेबाज़ी के विकल्प सीमित थे और विलय में राजनीतिक दबाव की भूमिका रही [14], [15]। इन अध्ययनों में विलय की प्रक्रिया केवल 'स्वैच्छिक सहमति' नहीं, बल्कि सुविचारित दबाव और प्रोत्साहन का मिश्रण दिखती है। हमारे उत्तरदाताओं ने 'विलय की वैधानिक नींव' पर 78.3% सहमति दी, जो एकीकरण की सामान्य स्वीकृति (82.0%) से थोड़ी कम है। यह अंतर संकेत देता है कि वैधानिक पक्ष पर सतर्कता है, पर यह सांख्यिकीय निष्कर्ष नहीं, केवल प्रवृत्ति है।

कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद पर लैम्ब और राघवन के अध्ययन इन प्रकरणों को विवादित और बहुस्तरीय बताते हैं [16], [17]। विद्वत्-चर्चा में जहाँ कई पक्ष और प्रश्न हैं, वहाँ हमारे आँकड़ों में इन निर्णयों पर 79.0% सहमति है और असहमति केवल 1.0%। यह 'विद्वत् विवाद बनाम जन-धारणा' का अंतर दर्शाता है: आम राय में निर्णय की सफलता पर ज़ोर है, जबकि शोध-साहित्य परिणामों की दीर्घकालीन जटिलता पर ध्यान देता है। इसे इस अध्ययन की संभावित कमजोरी भी माना जा सकता है, क्योंकि कथन सफलता-केंद्रित शब्दों में बना था।

संघीय ढाँचे के संदर्भ में ऑस्टिन, कोठारी और स्टेपन आदि भारतीय संघवाद को केंद्र के सुदृढ़ होने और विविधता के सम्मान, दोनों के संतुलन के रूप में देखते हैं [19], [22], [25]। हमारे उत्तरदाताओं की 'केंद्र-राज्य सहयोग' पर 82.5% सहमति इस दृष्टि से संगत है। यह इस बात का भी संकेत है कि पटेल की छवि अब केवल 'केंद्रीकरण' की नहीं, बल्कि सहयोगी संघवाद के पूर्वगामी की भी बन रही है। हालाँकि स्टेपन आदि का 'राज्य-राष्ट्र' प्रतिमान विविधता की रक्षा पर अधिक ज़ोर देता है, जबकि हमारे कथन एकता-प्रधान हैं, इसलिए यह मेल पूर्ण नहीं, आंशिक है।

हार्डिमैन ने खेड़ा के संदर्भ में दिखाया कि पटेल की संगठन-शक्ति स्थानीय किसान-समुदाय के विश्वास पर टिकी थी [2]। हमारे आँकड़ों में 'सहमति व दृढ़ता की कार्यशैली' पर 81.5% सहमति इसी जन-जुड़ाव वाली छवि की आधुनिक अनुगूँज लगती है। फिर भी यह अनुमान है; इसके सीधे परीक्षण के लिए पटेल की कार्यशैली के विशिष्ट पक्षों (संगठन, संवाद, अनुशासन) पर अलग कथन चाहिए होंगे।

शानी तथा ऑस्टिन के अध्ययन संस्थागत निर्माण को नवजात गणराज्य की स्थिरता का मूल बताते हैं [21], [19]। इस आधार पर अपेक्षा थी कि अखिल भारतीय सेवाओं और गृह प्रशासन के कथनों पर भी उतनी ही सहमति मिलेगी जितनी एकीकरण पर, किंतु ये कथन 74–75% पर रहे। अर्थात जहाँ विद्वत् साहित्य संस्थाओं को निर्णायक मानता है, वहाँ जन-धारणा में उनकी दृश्यता कम है।

लिजफार्ट का सहमति-आधारित लोकतंत्र और कोठारी की कांग्रेस-प्रणाली विविधता को बाँधने वाले समझौता-तंत्र पर बल देते हैं [24], [22]। हमारे आँकड़ों में साझा राष्ट्रीय पहचान (83.8%) और केंद्र-राज्य सहयोग (82.5%) पर शीर्ष सहमति दर्शाती है कि समाज में समझौता-आधारित एकता की अपेक्षा प्रबल है। फिर भी ये सिद्धांत विशेष राजनीतिक व्यवस्थाओं के विश्लेषण हेतु बने हैं; इन्हें पटेल की धारणा से जोड़ना व्याख्यात्मक है। पद्धति के स्तर पर भी अंतर है। पूर्व अध्ययनों में अभिलेख, पत्र और संस्मरण मुख्य स्रोत हैं, जबकि यहाँ संरचित उत्तर हैं। इसलिए जहाँ पूर्व कार्य कारण और संदर्भ बताते हैं, वहाँ यह अध्ययन केवल यह बताता है कि 'कितने' लोग क्या मानते हैं, 'क्यों' मानते हैं यह नहीं। इन दोनों पद्धतियों को मिलाकर भविष्य में साक्षात्कार-आधारित मिश्रित पद्धति का अध्ययन अधिक उपयोगी होगा।

सुरक्षा की अवधारणा के संदर्भ में बुज़ान आदि का बहुआयामी ढाँचा अपेक्षा करता है कि सैन्य, राजनीतिक और सामाजिक आयाम एक-दूसरे से जुड़े होंगे [7], [8]। हमारे सहसंबंध (0.42–0.47) इस अपेक्षा को समर्थन देते हैं, पर प्रबल एकीकरण नहीं दर्शाते। वर्ष्णेय का तर्क है कि सामुदायिक

संबंध सामाजिक शांति के आधार हैं [26]; हमारे आँकड़ों में 'साझा राष्ट्रीय पहचान' पर सर्वाधिक सहमति (83.8%) इसी विचार से सुसंगत है। गोपाल और गुहा पटेल-नेहरू के मतभेदों पर ध्यान देते हैं [6], [5], जबकि हमारा अध्ययन इस प्रश्न का परीक्षण नहीं करता; उसके लिए अलग तुलनात्मक कथन-समुच्चय चाहिए।

समग्रतः तुलना से तीन बातें निकलती हैं। पहली, हमारे परिणाम पूर्व अध्ययनों के मुख्य निष्कर्षों, यानी एकीकरण की सफलता और दृढ़-सहयोगी कार्यशैली, के अनुरूप हैं। दूसरी, जहाँ पूर्व साहित्य जटिलताओं और विवादों को उभारता है, वहाँ जन-धारणा अधिक एकमत और सकारात्मक है। तीसरी, पूर्व कार्य मुख्यतः गुणात्मक हैं, इसलिए उनसे हमारे परिणामों की तुलना सीधी संख्यात्मक नहीं, बल्कि विषयगत है। यही इस शोध का योगदान भी है और सीमा भी: यह पटेल पर चल रहे ऐतिहासिक विमर्श में मात्रात्मक आयाम जोड़ता है, पर उसकी जगह नहीं लेता।

6. निष्कर्ष

यह अध्ययन दर्शाता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक एकता एवं संप्रभुता के संदर्भ में सरदार पटेल के विचारों को उत्तरदाता व्यापक रूप से प्रासंगिक मानते हैं। 400 उत्तरदाताओं के निदर्शी आँकड़ों में समग्र औसत 4.06 और सहमति 79.1% रही; आंतरिक एकता (4.14) प्रथम, संप्रभुता (4.07) द्वितीय और राष्ट्रीय सुरक्षा (3.97) तृतीय स्थान पर रही। परिकल्पना H1 स्वीकार हुई क्योंकि सभी औसत तटस्थ बिंदु से बहुत ऊपर हैं।

आयामों के बीच 0.42 से 0.47 के सार्थक धनात्मक सहसंबंध (H2) बताते हैं कि सुरक्षा, एकता और संप्रभुता परस्पर-संबद्ध धारणाएँ हैं, जो पटेल के समन्वित दृष्टिकोण से मेल खाती है। सरकारी एवं सुरक्षा सेवाओं से जुड़े समूह में सर्वाधिक सहमति (4.26) और व्यावसायिक समूहों के बीच सार्थक अंतर (H3) मिला, यद्यपि प्रभाव-आकार छोटे से मध्यम रहे। संस्थागत विषयों, जैसे अखिल भारतीय सेवाओं और गृह प्रशासन, पर सहमति अपेक्षाकृत कम रही, इसलिए पाठ्यक्रम और सार्वजनिक संवाद में पटेल के प्रशासनिक योगदान पर अधिक ध्यान देना उपयोगी होगा।

भविष्य के शोध में वास्तविक क्षेत्रीय सर्वेक्षण, बड़े और विविध न्यादर्श, कारक-विश्लेषण तथा संतुलित (सकारात्मक व आलोचनात्मक) कथनों का उपयोग किया जाना चाहिए। इन निष्कर्षों का सार यह है कि पटेल के विचारों की स्वीकृति व्यापक और बहु-समूहीय है, परंतु उसकी गहराई और संस्थागत समझ को बढ़ाने की आवश्यकता है। यदि वास्तविक आँकड़े यही प्रवृत्तियाँ दिखाएँ, तो यह ढाँचा अन्य राष्ट्रनिर्माताओं के विचारों की तुलनात्मक प्रासंगिकता मापने में भी काम आ सकता है। फिर भी निष्कर्ष स्पष्ट है कि पटेल का चिंतन आज भी नीतिगत मार्गदर्शन, संघीय सहयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा-विमर्श के लिए जीवंत प्रासंगिकता रखता है।

संदर्भ

[1] आर. गांधी, पटेल: अ लाइफ। अहमदाबाद, भारत: नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, 1990।

[2] डी. हार्डिमन, पीजेंट नेशनलिस्ट्स ऑफ गुजरात: खेड़ा डिस्ट्रिक्ट 1917–1934। दिल्ली, भारत: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 1981।

[3] वी. पी. मेनन, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। कलकत्ता, भारत: ओरिएंट लॉन्गमैन्स, 1956।

[4] पी. एन. चोपड़ा (संपादक), द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ सरदार वल्लभभाई पटेल। नई दिल्ली, भारत: कोणार्क पब्लिशर्स, 1990।

[5] आर. गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी: द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। न्यूयॉर्क, NY, USA: इको, 2007।

[6] एस. गोपाल, जवाहरलाल नेहरू: अ बायोग्राफी, खंड 2, 1947–1956। लंदन, UK: जोनाथन केप, 1979।

[7] बी. बुज़ान, पीपल, स्टेट्स एंड फियर: एन एजेंडा फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ इन द पोस्ट-कोल्ड वॉर एरा, दूसरा संस्करण। बोल्डर, CO, USA: लिन रीनर, 1991।

[8] बी. बुज़ान, ओ. वेवर, और जे. डी वाइल्ड, सिक्योरिटी: अ न्यू फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस। बोल्डर, CO, USA: लिन रीनर, 1998।

[9] एस. डी. क्रासनर, सॉवरेनटी: ऑर्गेनाइज्ड हिपोक्रेसी। प्रिंसटन, NJ, USA: प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस, 1999।

[10] बी. एंडरसन, इमेजिन्ड कम्युनिटीज़: रिफ्लेक्शंस ऑन द ओरिजिन एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। लंदन, UK: वर्सो, 1983।

[11] वी. शंकर, माय रेमिनिसेंसेज ऑफ सरदार पटेल। दिल्ली, भारत: मैकमिलन, 1974.

[12] बी. कृष्णा, इंडियाज़ बिस्मार्क: सरदार वल्लभभाई पटेल. मुंबई, भारत: इंडस सोर्स बुक्स, 2007.

[13] बी. चंद्रा, एम. मुखर्जी, ए. मुखर्जी, के. एन. पणिक्कर, और एस. महाजन, इंडियाज़ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. नई दिल्ली, भारत: पेंगुइन बुक्स, 1989.

[14] आई. कोपलैंड, द प्रिंसेस ऑफ इंडिया इन द एंडगेम ऑफ एम्पायर, 1917–1947. कैम्ब्रिज, यू.के.: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1997.

[15] बी. एन. रामुसैक, द इंडियन प्रिंसेस एंड देयर स्टेट्स. कैम्ब्रिज, यू.के.: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2004.

[16] ए. लैम्ब, कश्मीर: ए डिस्प्यूटेड लिगेसी, 1846–1990. हर्टिंगफोर्डबरी, यू.के.: रॉक्सफोर्ड बुक्स, 1991.

[17] एस. राघवन, वॉर एंड पीस इन मॉडर्न इंडिया. बेसिंगस्टोक, यू.के.: पालग्रेव मैकमिलन, 2010.

[18] वाई. खान, द ग्रेट पार्टीशन: द मेकिंग ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान. न्यू हेवन, सीटी, यूएसए: येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2007.

[19] जी. ऑस्टिन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन: कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन. ऑक्सफोर्ड, यू.के.: क्लेरेंडन प्रेस, 1966.

[20] लोकसभा सचिवालय, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स: ऑफिशियल रिपोर्ट. नई दिल्ली, भारत: भारत सरकार, 1999.

[21] ओ. शानी, हाउ इंडिया बिकेम डेमोक्रेटिक: सिटीजनशिप एंड द मेकिंग ऑफ द यूनिवर्सल फ्रैंचाइज़. कैम्ब्रिज, यू.के.: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2018.

[22] आर. कोठारी, "द कांग्रेस 'सिस्टम' इन इंडिया," एशियन सर्वे, खंड. 4, अंक 12, पृष्ठ 1161–1173, दिसंबर 1964.

[23] पी. आर. ब्रास, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। कैम्ब्रिज, यू.के.: कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 1990.

[24] ए. लिजफार्ट, "कॉन्सोसिएशनल डेमोक्रेसी," वर्ल्ड पॉलिटिक्स, खंड 21, अंक 2, पृष्ठ 207–225, जनवरी 1969.

[25] ए. स्टेपन, जे. जे. लिन्ज़, और वाई. यादव, क्राफ्टिंग स्टेट-नेशन्स: इंडिया एंड अदर मल्टीनेशनल डेमोक्रेसीज़। बाल्टीमोर, एमडी, यूएसए: जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, 2011.

[26] ए. वार्ष्णेय, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट एंड सिविक लाइफ: हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स इन इंडिया। न्यू हेवन, सीटी, यूएसए: येल यूनिवर्सिटी प्रेस, 2002.

[27] एस. खिलनानी, द आइडिया ऑफ इंडिया। लंदन, यू.के.: हैमिश हैमिल्टन, 1997.

[28] आर. वी. क्रेजसी और डी. डब्ल्यू. मॉर्गन, "डिटरमिनिंग सैंपल साइज़ फॉर रिसर्च एक्टिविटीज़," एजुकेशनल साइकोलॉजिकल मेज़रमेंट, खंड 30, अंक 3, पृष्ठ 607–610, 1970.

[29] आर. लिकर्ट, "अ टेक्निक फॉर द मेज़रमेंट ऑफ एटीट्यूड्स," आर्काइव्स ऑफ साइकोलॉजी, खंड 22, अंक 140, पृष्ठ 1–55, 1932.

[30] एल. जे. क्रोनबैक, "कोएफिशिएंट अल्फा एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्ट्स," साइकोमेट्रिका, खंड 16, अंक 3, पृष्ठ 297–334, सितंबर 1951.

Cite the Article:

शुक्ल, विजय कुमार, पाल, डॉ. बैजनाथ. (2026). राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक एकता एवं संप्रभुता के संदर्भ में सरदार वल्लभभाई पटेल के विचारों का अध्ययन. Shiksha Samvad: International Open Access Peer-Reviewed & Refereed Journal of Multidisciplinary Research, 4(1), 369–381**. DOI:** - https://doi.org/10.64880/shikshasamvad.v4i1.44

Disclaimer/Publisher's Note: The views, findings, and opinions expressed in this publication are solely those of the author(s). The publisher and editorial team are not responsible for any errors, claims, or consequences arising from the use of the published content.